



भारत का गज़त

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

No. 79] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 1990/फालगुन 10, 1911

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1990/PHALGUNA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे इक यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

उपाधिकार

(राजस्व विभाग)

अय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्तन को रोकने के लिए

(विदेश कर प्रभाग)

भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच अभिसमय भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्तन को रोकने के लिए एक नया अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है:

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1990

आय-कर

अनुच्छेद 1

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दोनों सरकारों राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

1 जो कर इस अभिसमय के विषय हैं, वे इस प्रकार हैं :-

(क) जापान में :

(i) आयकर; और

(ii) निगम कर।

(इन्हें इसके बाद “जापानी कर” कहा गया है) ;

(ब) भारत में :

आयकर, जिसमें उस पर, लगाया गया कोई अभिधार भी शामिल है।

(जिसे इसके बाद “भारतीय कर” कहा गया है)।

2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सार्थक: इसी तरह के करों गर भी लागू होगा, जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पञ्चात् पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महावृपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में, ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् एक समुचित अवधि के भीतर, एक दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने करशान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद 3

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) “जापान” शब्द से अभिप्रेत है जब एक भौगोलिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है जापान का राज्य क्षेत्र जिसमें यह भी शामिल है—राज्य क्षेत्रीय समूद्र जिस पर जापानी कर से संबंधित कानून लागू होता है, राज्य क्षेत्रीय समूद्र से परे समस्त क्षेत्र जिसमें उसका समुद्रतल तथा अवमृद्धि भी शामिल है, जिस पर जापान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार धेनाधिकार रखता है तथा जिसमें जापानी कर से संबंधित कानून प्रवृत्त हैं;

(छ) “भारत” शब्द से अभिप्रेत है—भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है—राज्य क्षेत्रीय समूद्र तथा कोई भी अन्य समूद्री क्षेत्र जिसके बारे में भारत को भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न धर्मिकार प्राप्त है;

(ग) “एक संविदाकारी राज्य” तथा “दूसरा संविदाकारी राज्य” पदों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार जापान अथवा भारत अभिप्रेत है;

(घ) “कर” शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार जापानी कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है;

(ङ) “व्यक्ति” शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी और व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है;

(च) “कम्पनी” शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत हैं जिसे कर-प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(छ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” और “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) “राष्ट्रिक” शब्द से अभिप्रेत है:-

(i) जापान के बारे में :

सभी व्यक्ति जिन्हें जापान की राष्ट्रिकता प्राप्त है और सभी विधिक व्यक्ति जिनका सूचन अथवा संगठन जापान के कानूनों के अन्तर्गत हुआ हो तथा ऐसे सभी विधिक व्यक्तित्व वाले संगठन जिन्हें जापान के कानूनों के अन्तर्गत जापानी कर के प्रयोजनार्थ सूचित अथवा संगठित किए गए विधिक व्यक्तियों के रूप में मान गया हो।

(ii) भारत के बारे में :

(क) ऐसे मध्ये व्यक्ति जिन्हें भारत की राष्ट्रिकता प्राप्त हो;

(ख) ऐसे सभी विधिक व्यक्ति भारतीयता, तथा संघ जिन्हें भारत में प्रवृत्त कानूनों से इस तरह की हैमियत प्राप्त हो,

(ज) “अन्तर्राष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो मिलाय उस स्थिति के जब उक्त जलयान अथवा वायुयान के द्वारा संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच हो चलाया जाता हो ; और,

(झ) “सक्षम प्राधिकारी” पद से अभिप्रेत है:

(i) जापान में, वित्त मंत्री अथवा, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ii) भारत में, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ।

2. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी धर्मावली का जो उसमें परिभाषित नहीं हुई हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है। जिन पर ये अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद 4

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, “किसी संविदाकारी राज्य का निवासी” पद में अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके धर्मावल, निवास, प्रबंधन्यान अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य कस्टौटी के कारण वहाँ पर कर लगाया जा सकता है।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हो, वहाँ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहभागि से उस संविदाकारी राज्य का निर्धारण करेंगे जिस राज्य का वह व्यक्ति इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ एक निवासी समझा जाएगा।

अनुच्छेद 5

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ “स्थायी संस्थापन” पद से करोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ किसी उद्यम का करोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाते हैं।

2. “स्थायी संस्थापन” पद के विवेषयतः निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारबाना ;

(ङ) कोई कार्यालया ;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस या कोई कुआं कोई खदान अथवा प्राकृतिक संवधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(छ) कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्ति द्वारा कोई भाण्डागण सुविधाएँ सुहैया करता हो ;

(ज) कोई कार्म, बर्गीचा अथवा अन्य स्थान जहाँ पर कृषि, बानिकी पौधे उगाने अथवा उनसे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ;

(झ) कोई भाण्डार अथवा अन्य विक्री केन्द्र ; तथा

(अ) कोई संस्थापन। अथवा संरचना जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक संसद्धनों की खोज के लिए, किया जाता हो, किन्तु केवल उस स्थिति में जब उसका इस्तेमाल छः महीने की अवधि से अधिक समय तक किया गया हो।

3. कोई भवन स्थल अथवा निर्माण, संस्थापन। अथवा ऐसेभन्नी प्रोजेक्ट केवल उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन होगा यदि वह छः महीने से अधिक समय तक विद्यमान रहता है।

4. किसी उद्यम का किसी संविदकरी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार का चलाया जाना। तभी समझा जाएगा यदि वह उस तंत्रिकाकरी राज्य में किसी निर्माणस्थल अथवा निर्माण, संस्थापन। अथवा ऐसे ऐसेभन्नी प्रोजेक्ट के संबंध में छः महीने की अवधि से अधिक समय तक पर्यावरण कार्यकलाप चलाता हो जो उस संविदकरी राज्य के भीतर यह किए जाते हों।

5. पैराग्राफ 3 तथा 4 के उपबंधों के होते हुए भी किसी उद्यम का किसी संविदकरी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार का चलाया जाना तभी माना जाएगा यदि वह उस संविदकरी राज्य में उस तंत्रिकाकरी राज्य के अतिरिक्त खनिज तत्वों की खोज, उनके सनुयोजन अथवा निर्कर्षण के बारे में छः महीने को अवधि से अधिक समय के लिए सेवाएं अथवा सुविधाएं प्रदान करता है।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंधों के होते हुए भी “धार्यी संस्थापन” पद से निम्नलिखित का शामिल नहीं होना। माना जाएगा :

(क) उस उद्यम से सबधित माल अथवा पर्यावरण वस्तुओं के भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ माल सुविधाओं का इस्तेमाल करना;

(ख) माल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पर्यावरण वस्तुओं के किसी स्टाक का रख-रखाव करना;

(ग) माल किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधन किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पर्यावरण वस्तुओं के किसी स्टाक का रख-रखाव करना;

(घ) उस उद्यम के लिए माल अथवा पर्यावरण वस्तुओं की माल खरीद करने अथवा उसके बारे में सूचना एकत्र करने के लिए व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(ङ) उस उद्यम के लिए माल किसी प्रारंभिक अथवा सहायक किस्म के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना।

7. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहां पर कोई स्वतंत्र हैसियत किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति दूसरे संविदकरी राज्य के किसी उद्यम को तरफ से किसी तंत्रिकाकरी राज्य में कार्य करता हो, उस उद्यम का प्रयोग-निलिखित तंत्रिकाकरी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा :

(क) यदि उसे उस उद्यम की तरफ से उस संविदकरी राज्य में ठेकों को सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो तथा वह आदतन ऐसे ठेके सम्पन्न करता हो, जब तक कि इसके कार्य कालाप, यदि उन्हें कारोबार के किसी निश्चित स्थान पर सम्पन्न किया गया हो, पैराग्राफ 6 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित नहीं हों, जिसके द्वारा कारोबार का यह निश्चित स्थान उस पैराग्राफ के उपबंधों के तहत एक स्थायी संस्थापन नहीं बनेगा;

(ख) उनके पर सह तरह का कार्ड प्राधिकार नहीं हो किन्तु वह प्रथमोलिनिखित संविद करी राज्य में ऐसे माल अथवा पर्यावरण वस्तुओं का एक स्टक अदान रखता हो जिसमें से वह नियमित रूप से इस उद्यम को तरफ से माल अथवा पर्यावरण वस्तुओं को डिलवरी करता हो; अथवा

(ग) वह उस प्रथमोलिनिखित निविदकरी राज्य में अदान आदेश प्राप्त करता हो, पूर्णतः अथवा लाभग पूर्णतः स्वप्रं उस उद्यम के लिए अथवा उद्यम के लिए और ऐसे उद्यमों के लिए जो नियंत्रण रखते हों, नियंत्रण में रहते हों, अथवा उस उद्यम की तरह उस जैसे नियंत्रण में रहते हों।

8. किसी उद्यम का किसी तंत्रिकाकरी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना मव इस कारण नहीं माना जाएगा कि वह किसी दलाल, सामान्य कानूनी एजेंट अथवा किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट की मार्फत उस तंत्रिकाकरी राज्य में व्यापार चलाता हो बश्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार की समान्य प्रक्रिया में कार्य करते हो।

9. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी जो किसी तंत्रिकाकरी राज्य का निवासी है किसी ऐसी कम्पनी पर नियंत्रण रखती अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे तंत्रिकाकरी राज्य की निवासी हो अथवा जो दूसरे तंत्रिकाकरी राज्य में (चहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार चलाता हो, दोनों में से किसी भी कम्पनी को दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन का दर्जा नहीं देता।

अनुच्छेद 6

1. एक तंत्रिकाकरी राज्य के किसी द्वारा दूसरे संविदकरी राज्य में स्थित अचल तपति से प्राप्त आय पर उस दूसरे तंत्रिकाकरी राज्य में कर लाया जा सकेगा।

2. “अचल सम्पत्ति” पद का अर्थ ही होगा जो उस संविदकरी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसकी अर्थ है जिसमें सबधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी दणा में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वनिकों से प्राप्त पश्चिम और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर अचल सम्पत्ति लंबी सामान्य कानून के उपबद्ध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भी जो के अधिकार और खनिज भण्ड रों, स्वातंत्र तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए, अथवा कार्य के अधिकार के प्रतिकल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार; जलयान तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

1. किसी संविदकरी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी संविदकरी राज्य में कर लाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदकरी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरोंके में कारोबार चलाता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे नंविदकरी राज्य में कर लाया जा सकता है, किन्तु उनके लाभों के केवल उतने आय पर ही कर लाया जा सकता है जो प्रत्यक्षतः अव्यवहारः उस स्थायी संस्थापन के कारण हो।

2. पैर ग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहने हुए जहाँ एक संविदाकारी राज्य क: कोई उद्यम दूसरे संविदाकरी राज्य से स्थित किसी स्थायी संस्थापन के मध्यम से करोड़ लाख लाख लाख में ऐसे लाभों को उस स्थायी संस्थापन के लाभ समझा जाएगा जो उसे उस स्थिति में प्राप्त होने के अधीक्षण रहते। जब वह एक समन्वयक उससे भिन्नता-जुलती पारिवर्तनों में एक समन्वय या उससे भिन्नता-जुलते कार्यकालों में लाभ हुआ कोई निश्चित और अधिक उद्यम होता और उस उद्यम के सभी पूर्णतया खत्तंत रूप से करोड़ लाख लाख का यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन उच्चों को कटोरियों के रूप में अनुमति दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजन थे किए गए हों, जिनमें इस प्रकार से किए कार्यकारी तथा समान्वय प्रण कर्त्तव्य भी शमिल हों, जहाँ वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ वह स्थायी नियन्त्रण व्यवस्था अन्वय किए गए हों।

4. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में यह प्रथा नहीं है कि किसी स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभों का निर्धारण उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में विभाजन के आवार पर किया जाता हो, वहाँ पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य की प्रथा अनुसार विभाजन के द्वारा कर्योग्य लाभों का निर्धारण करने से निर्धारित नहीं करेगी; तथापि विभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसों होगी कि उसके परिणाम इस अनुच्छेद में विविहत सिद्धान्तों के अनुकूल होंगे।

5. कोई भी ऐसा लाभ मात्र इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए मात्र अथवा पथ्य वस्तुएं खरीदी गई हैं।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंधों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक वर्षनिवृत्त उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं होंगे।

7. जहाँ पर लाभों में आय की ऐसी मद्देन शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ पर उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के से प्राप्त लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, ऐसे लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जहाँ से कराराय प्रथम दस वर्षों की अवधि के दौरान अथवा “पूर्ववर्ती वर्षों” में, जैसा भी मामला हो, प्राप्त हुए हों, जिस अवधि के लिए यह अभिसमय प्रभावों होगा वर्षों कि इस प्रकार प्रभावित कर की सीमा निम्नलिखित से अधिक नहीं हो।

(क) प्रथम पांच वर्षों के दौरान, 50 प्रतिशत;

(ख) शेष पांच वर्षों के दौरान, उस दूसरे संविदाकारी राज्य के काराधान कानून के द्वारा अन्यथा लगाए गए कर की मात्रा का 25 प्रतिशत।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंध किस पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी में भागादारिया से प्राप्त लाभों पर भी लाग होंगे।

5. अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी इस अनुच्छेद के उपबंध जापान में उद्यम कर पर भी लाग होने के गाथनाथ उग उद्यम कर से मिलने-जुलते किसी कर पर भी उस स्थिति में लाग होने जहाँ कभी ऐसा कर भारत में लगाया गया ही।

अनुच्छेद 9

1. जहाँ :

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी के सिनसिने में प्रत्यक्षः अवश्य अप्रत्यक्षः भाग लेता है, अथवा

(ख) वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी के सिनसिने में प्रत्यक्षः अवश्य अप्रत्यक्षः भाग लेते हैं;

दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखा अथवा लगाई जाती हों, जो ऐसी शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखा जाना हो, तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की दशा में दोनों उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता परन्तु उस शर्तों के कारण वह इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, उम उद्यम के लाभों में समिलित किया जा सकेगा और तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहाँ पर एक संविदाकारी राज्य उम संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को समिलित करा है और तदनुसार कर लगाता है—जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के यकीपी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और जहाँ पर संविदाकारी राज्यों के भवय प्राधिकारी विद्यार्थिमय करने के पश्चात् इस वात पर सहमत होते हैं कि इस प्रकार समाहित किए गए कुल लाभ अथवा लाभों का कोई अंग ऐसे लाभ हैं जो प्रवयोत्तिविल्वा संविदाकारी राज्य के उस उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हगए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच बनाई गई शर्तें इस तरह क होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई गई होती ती वह दूसरा संविदाकारी राज्य उस तरह से सहमत प्राप्त लाभों पर, उन पर प्रभावित कर की मात्रा के अनुगार समुचित समायोजन करेगा। इस तरह का समायोजन करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों पर गथीचित ध्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद 10

1. किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए नाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में करार्धेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उम संविदाकारी राज्य में भी करार्धेय होंगे, जिसको लाभांश अदा करने वाली कम्पनी उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुगार वहाँ निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभोगी स्वामी है, तो इस प्रकार के प्रभावित कर की रकम उक्त लाभांशों का सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इस पैराग्राफ के उपबंध उस कम्पनी के उन लाभों से संबंधित करार्धेय को प्रभावित नहीं करे, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “लाभांशों” शब्द का अभिप्राय है— शेषों अथवा अधिकारों से, जो क्रष्ण-दावे नहीं हों, जो लाभ में शामिल हों, प्राप्त आय, तथा अन्य नियमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार के कराराधान व्यवस्था लगू होती है जो उम संविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा शेषों से प्राप्त आय के मामले में लाग होती है जिसमें वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराश्राफ 1 और 2 के उत्तर उन पिंडी में जा गए हैं। यदि लाभांशों का हितभोग रकमी, जो किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ पिंड ; किसी स्थायों संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसको लाभांश अदा करने वालों कंपनी निवासी है, अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस मप्पति के संबंध में लाभांशों को अदायगों को जातो है वे इग प्रकार के स्थाया संस्थापन प्रथा निश्चित स्थान से प्रभावों रूप से वस्तुद्ध हैं। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 प्रथा अनुच्छेद 14 जैसा भी मामला हो, के उबंध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य के लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसे मामले में उस कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर जहाँ तक ऐसे लाभांशों को छोड़कर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हैं, अथवा जहाँ तक कि ऐसी संपत्ति के बारे में ! पांचों को अदायगों को गई हो, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हिस्तो स्थायों संस्थापन अथवा अनुच्छेद स्थान से प्रभावों रूप से सम्बद्ध है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न हो कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभकर को किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, भले ही अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अशतः उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उत्तम होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हो हों।

अनुच्छेद 11

1. किसी संविदाकारी राज्य में उत्तम होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा, जिस राज्य में यह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभास्ति कब को राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :

(क) ब्याज को सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि हितभोगी स्वामी बैंक है ; और

(ख) सभी अन्य मामलों में ब्याज को सकल राशि का 15 प्रतिशत।

3. पैराश्राफ 2 के उत्तरों के होते हुए भी किसी एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजनीतिक उत्तरों अथवा स्थानीय प्राधिकरण, दूसरे संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय बैंक संघर्षों उस सरकार के पूर्णतः समर्पित वालों किसी वित्तीय संस्था द्वारा गारंटीशूट अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टिपूर्ण क्रण-दावों के संबंध में उद्भूत तथा उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, उस दूसरे राज्य के केन्द्रीय बैंक अथवा उस सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वालों किसी वित्तीय संस्था द्वारा अथवा उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य के किंतु निवासी द्वारा प्राप्त ब्याज को प्रथमोलिंगिट संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

4. पैराश्राफ 3 के प्रयोगजार्य, "केंद्रोप्र बैंक" तथा "संकार" के पूर्णतः स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था" पद का अभिप्राय :

(क) जापान के मामले में :

- (1) दि बैंक आफ जापान
- (2) जापान का नियान-याया बैंक ;
- (3) समुद्रारोय आधिक भव्योग निधि ;
- (4) जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण ; और

(5) ऐसो अन्य वित्तीय संस्था, जिसको पूंजी का स्वामित्व पूर्णतया जापान सरकार द्वारा धारित हो, जो दोनों संविदाकारी राज्यों के सरकारों के बीच समय-नमय पर महसून हो ;

(ख) भारत के मामले में :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक ;

(2) भारत का नियान-याया बैंक ;

(3) ऐसो अन्य वित्तीय संस्था, जिसको पूंजी भारत सरकार द्वारा पूर्णतया धारित हो तथा दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच समय-नमय पर सहमत हों।

5. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है— प्रत्येक प्रकार के क्रृष्ण-दावों में प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों या नहीं हों, और चाहे क्रृष्ण-दावों के लाभों में भागोदारी का कोई अधिकार रखने हों या नहीं रखते हों, और खासतीर पर, गरमारा प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधन-पत्रों अथवा क्रृष्ण-दावों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधन-पत्रों अथवा क्रृष्ण-दावों से संबंधित प्राप्तियम और पुरस्कार भी शामिल हैं।

6. पैराश्राफ 1, 2 और 3 के उत्तर उन पिंडी में जागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज, प्रतिभूत हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायों संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस क्रृष्ण-दावों के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायों संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्राप्त रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में प्रनुच्छेद 7 अथवा 14 के उत्तरबंध यथास्थिति लागू होंगे।

7. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उस स्थिति में उद्भूत हुआ समझा जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस संविदाकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थाया संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान है जिसके संबंध में वह क्रृष्ण उद्भूत हुआ हो, जिस पर ब्याज को अदायगों की गई हो और इस प्रकार का ब्याज ऐसे स्थाया संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इन प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थाया संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

8. जहाँ ब्याज अदाकर्ता नथा हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बाच कोई विशेष प्रकार का संबंध होते के कारण अदा कोई ब्याज को रकम, उस क्रृष्णदावे को श्याम में रखते हुए, जिसके लिए उस ब्याज को रकम अदा को गई है, उस रकम से बड़ जाती है जिसके लिए इस प्रभाग के संबंधों के नहीं होने का यिदी। अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच सहमति हो गई होता वहाँ इसमें प्रनुच्छेद के उत्तरबंध केवल अन्तिम वर्णित नायि पर हो लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगों के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उत्तरबंधों का सम्पर्क ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुयार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 12

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा को जाने वाली रायलिट्यों तथा तकनीकों सेवाओं के लिए फास के भुगतान पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

की सेवाओं के लिए फोस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होता है तथा उसी संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुमार, कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्त-कर्ता रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस का हितभोगी स्थानी है तो इस प्रकार लगाए गए कर को राशि उक्त रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस की सकल राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “रायलिट्यों” शब्द से माहितिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक वृत्तियों, जिनमें चलचित्र, फिल्में तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में तथा टेबें भी शामिल हैं, कोई पेटेन्ट ट्रॉडमार्क, डिजाइन अथवा माडल, एजान, गूप्त कार्मस्ला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, कापी राइट के लिए अथवा ग्रीडोगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपरकर अथवा ग्रीडोगिक, धारणज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए उसके प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए फोस” पद से अभिप्रेत है, किसी प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के प्रतिकल में अनुच्छेद 14 में उल्लिखित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के लिए अदायगियां करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्मचारी को को जाने वाली अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को तथा किसी व्यष्टि को की गई किसी किस्म की अदायगियां।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए हितभोगी रवासी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें यायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस उद्भूत होतो है वहाँ पृथक् स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ निष्पन्न करता हो तथा जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा ठिकें के संबंध में रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस की अदायगी को जाती है, उसका संबंध प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से हो, ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. रायलिट्यों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस एक संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में उद्भूत हुई मानी जाएगी जब अदाकर्ता स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो। तथापि, जहाँ रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं है, उस संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान, जिसके संबंध में रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस अदा की जाती है और ऐसी रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस को ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहुन किया जाता है तो ऐसे रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस के लिए भुगतान, उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ अदाकर्ता और हितभोगी रवासी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस की रकम, रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस के भुगतान का उपयोग अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखने हुए, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार का संबंध नहीं होने काँ दशा में अदाकर्ता और हितभोगी रवासी सहमत हो गए होते, वहाँ पर इस अनुच्छेद के उपबंध केरल अन्तिम

वर्णित रकम पर हो लागू होंगे। ऐसे मामले में, अधिक अदा को गई रकम इस अभिसमय के अन्य उपबंधों पर व्योमित ध्यान देते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य होगी।

अनुच्छेद 13

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में रित्य अचल संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उम दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. अचल सम्पत्ति से भिन्न किसी ऐसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त हुए अभिलाभों पर, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी स्थायी संस्थापन को व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोगनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से संधित अचल संबंधि से भिन्न कोई सम्पत्ति हो, जिसमें ऐसे किसी स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा समूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. जब तक कि पैराग्राफ 2 के उपबंध लागू नहीं हों, तब तक किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो, के शेयरों के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तिम अभिलाभों पर उम दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा। . . .

4. किसी संविदाकरी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर राष्ट्रीय योग्यतानाम में चलए जाने वाले जलवानों अथवा वायुयानों के अन्तरण से तथा ऐसे जलवानों अथवा वायुयानों के परिचालन से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

5. किसी संविदाकरी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफ 1 से 4 तक में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

अनुच्छेद 14

1. किसी संविदाकरी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय तब तक उसी संविदाकरी राज्य में करार्धेय होगी, जब तक उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोगनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो अथवा वह किसी करार्धेय वर्ष अथवा “पिछले वर्ष” के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक को अवधि या अवधियों के लिए जैसा भी मामला हो, उस दूपरे संविदाकारी राज्य में नहीं रहा हो। यदि उसके पास उम दूसरे संविदाकरी राज्य में एक ऐसा निश्चित स्थान है अथवा उक्त अवधि या अवधियों के लिए वह रहत है, तो वह आय उम दूसरे संविदाकारी राज्य में करार्धेय होगी परन्तु केवल उतनी ही आय करार्धेय होगी, जो उक्त अवधि अथवा अवधियों के दौरान उस दूसरे संविदाकरी राज्य में उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जाती है अथवा प्राप्त होती है।

2. “व्यावसायिक सेवाएँ” पद के अर्थविस्तार में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, स हित्य, कलात्मक शैक्षि अथवा अध्यायन संबंधि कार्यकलापों के मध्यमात्रा चिकित्साकों, गल्य चिकित्साकों, वकीलों इंजीनियरों वास्तुविदों, दन्त चिकित्साकों और लेखात्मालों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त बेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो, यदि इस प्रकार का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहाँ से प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि

- (क) प्राप्तकर्ता किसी करा धेय वर्षे अथवा “द्विवर्ती वर्ष” जैसी भी मामला हो, के दोस्रा कुल मिलकार 183 दिन से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य में नौजवा रहा ही;
- (ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है, और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थानीय संस्थान अथवा किसी निश्चित स्थान से वहाँ नहीं किया गया हो, जो नियोजन के दूसरे संविदाकारी राज्य में है।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी उच्च द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वायांवान में किसी जलयान अथवा वायुयान पर सवार होकर उसके परिचलन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 16

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कम्पनी के निदेशक मण्डल के एक सदस्य को हैसियत में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस आर अन्य सम्पूर्ण अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 17

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी व्यष्टि द्वारा, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, मनोरंजनकर्ता के रूप में जैसे वियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार और किसी संगीतकार या किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार सम्पन्न किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

तथापि ऐसी आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से कृद प्राप्त होगी, यदि ऐसे कार्यकलाप किसी व्यष्टि द्वारा, जो प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य का निवासी है, जो संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए स्वीकृत किसी विशेष कार्यक्रम के अनुसरण में किए जाते हैं।

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी निवासी द्वारा अपने उस तरह की हैमियत से किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों से उद्भूत आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्रादृभूत नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति को होता है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो अनुच्छेद 7, 14, और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस आय पर कर प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में लग सकेगा।

तथापि, ऐसी आय पर उस प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में कर से कृद प्राप्त होगा, यदि ऐसे कार्यकलाप दो संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए स्वीकृत एक विशेष कार्यक्रम के अनुसरण के किए जाते हैं।

अनुच्छेद 18

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को विगत में नियोजन के प्रतिकल के रूप में प्रदत्त पेशनों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिकों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेगा।

अनुच्छेद 19

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए सरकारी स्वरूप के किहीं कार्यों को सम्पन्न की गई सेवाओं के तंबंध में अदा की गई पैशन से मिल पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में ही लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल उस स्थिति में लग सकेगा, यदि व्यष्टि उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती है और वह व्यष्टि उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, जो

(i) उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा

(ii) सेवाएं सम्पन्न करने के प्रयोजनार्थ केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं वह।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस संविदाकारी राज्य, अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए सम्पन्न की गई सेवाओं के तंबंध में नियोजियों द्वारा अदा की गई अथवा ऐसी नियोजियों में से, जिसके लिए अंशदान किया जाता है, अदा की गई किसी पैशन पर इस संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा।

(ख) तथापि ऐसी पैशन पर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर उस स्थिति में लगेगा, यदि व्यष्टि उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक है।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए करोंवार के तंबंध में सम्पन्न की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक और पैशनों पर लग जाएंगे।

अनुच्छेद 20

किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तथा जो प्रथमोंटिनिवित संविदाकारी राज्य में केवल अपने अनुसंधान, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्राप्त अदायगियों पर उस प्रथमोंटिनिवित संविदाकारी राज्य के कर से छूट प्राप्त होगा, वर्णते कि ऐसों अदायगियाँ उसे उस प्रथमोंटिनिवित संविदाकारी राज्य के बाहर से को जानी हैं।

अनुच्छेद 21

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य मान्य प्राप्ति अणिक संस्थामें अध्यापन अथवा अनुसंधान के प्रयोजनार्थ दो वर्ष से अनधिक को अधिक के लिए किसी संविदाकारी राज्य में अस्थायी रूप से दौरा करता है, तथा जो उस तरह के दौरे के तत्काल पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा या तो इस प्रकार के अध्यापन अथवा अनुसंधान के लिए प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. यह अनुच्छेद उस अनुसंधान कार्य से प्राप्त आय पर उस रिति में लागू नहीं होगा, यदि ऐसा अनुसंधान कार्य मार्वजनिक हित में नहीं किया जाना है किन्तु स्लतः वह कार्य किसी शास्त्री अथवा व्यक्तियों-विजेता के निजों लाभ के लिए किया जाना है।

अनुच्छेद 22

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर, जहाँ कहीं वे उत्पन्न होती हों, इस प्रभिममय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में जिन पर विचार नहीं किया गया हो, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में अथवा-परिभासित अचल ममति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होगे, यदि ऐसी आय को प्राप्त करने वाला किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस संविदाकारी राज्य में व्यापार चानाना है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ पर वह रिति किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैकितक मेवाएँ निष्पत्र करता है और जिस अधिकार अथवा मपति में प्राप्त होने वाली आय की अदायगी करता है, वह अधिकार अथवा ममति ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निष्पत्र स्थान से प्रसारी रूप से संबंधित है ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबन्ध जैसा भी मामला हो, लागू होगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होते हुए भी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर, जिन पर इस प्रभिममय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लकेगा।

अनुच्छेद 23

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कानून अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को नियंत्रित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों के जहाँ पर इसके विवरीत स्पष्ट उपबन्ध इस प्रभिममय में दिए गए हैं।

2. भारत के मामले में दौहरे कराधान का निम्न प्रकार से परिचार किया जाएगा :—

(क) जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस प्रभिममय के उपबन्ध के अनुसार जा सकता है, उसस्थिति में भारत उस निवासी को उस आय पर कर से कटौती की अनुमति उन्होंने रकम के बर बर देगा जिन्होंने रकम की अदायगी जापान में जमानी कर के लिए को गई हो, वहाँ वह प्रत्यक्ष स्थान से दिया गया हो या कठोरों के द्वारा दिया गया हो, हिंग शीर्सों पाठों में दोनों कटौती की मात्रा आपकर कठोरों दिए जाने से पूर्व यथा संगीत के उत्तरे भाग में अधिक नहीं होगा, जो यथास्थिति उस आय के कारण उत्तर हुई हो, जिस पर जापान में कर लगाया जा सकता है। इसके अनिरिक्त जहाँ ऐसा निवासी एक कम्पनी है, जिसके माध्यम से भारत में प्रतिक्रिया दी बनता हो, वहाँ जापान में या तो असा किसी गण आरक्ष के संबंध में कठोरों की अनुमति प्रथमतया उस कम्पनी द्वारा भारत में देय आय कर से देगा और जेप, रकम पर से यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में देय अनिकर से अनुमति देगा।

(ख) जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस प्रभिममय के उपबन्धों के अध्यधीन कराने जापान में कर लगाया जा सकता है, उसस्थिति में भारत इस आय को कर आवारा में शामिल करेगा लेकिन, आयकर में से आयकर के उन्हें भाग की कठोरों जैसा भी मामला हो, को अनुमति देगा जो जापान में उद्भूत हुई आय कारण बना हो।

3. जानानी कर को मदेनजर रखते हुए जापान से भिन्न किसी अव्य देश में देय कर पर क्रेडिट के रूपमें छूट के बारे में जापान के कानूनों के अध्यधीन रहते हुए :

(क) जहाँ जापान का कोई निवासी भारत से आय प्राप्त करता है, जिस पर इस प्रभिममय के उपबन्ध के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, उसस्थिति में उस आय के संबंध में देय भारतीय कर की राशि उस निवासी पर लगाए गए जापानी कर मात्रा के अनुसार क्रेडिट के रूप में, अनुमत्य होगी तथापि क्रेडिट की बह रकम जानानी कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय के लिए ममुचित हो।

(ख) जहाँ भारत से प्राप्त आय किसी कंपनी द्वारा जो कि भारत की निवासी है, एक ऐसी कम्पनी को जो जापान की निवासी है, और जिसके पास लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के वोर्टिंग जेयर के 25 प्रतिशत के अन्यून भाग का अथवा उस कम्पनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों का स्वामित्व है, अदा किया गया एक लाभांश हो, उस स्थिति में उस क्रेडिट की अपनी आय के संबंध में लाभांश अदा करने वाली कम्पनी द्वारा देय भारतीय कर के हिसाब में लिया जाएगा।

(ग) ऊपर उपर्युक्त शास्त्रों (क) और (घ) में उल्लिखित शैटिट के प्रयोजनार्थ करदाता द्वारा उस रकम को अदा किया गया माना जाएगा, जिसकी अदायगी भारत के कानून के अध्याधीन है और इस अनिमय के अनुसार भारतीय कर के स्पष्ट में उस स्थिति में को गई होती है, यदि अदा किए गए उस भारतीय कर को इस अनिमय पर हस्ताभृत होने के तरिके से लागू तथा भारत में आर्थिक विकास के लिए निर्मित किए गए विशिष्ट प्रोत्साहन कार्य के उपायों के अनुगार यह नहीं गया हो अथवा उनमें राहत नहीं दी गई हो अथवा जिन्हें मौजूदा उपायों के संगीत्यन में अथवा उनके अतिरिक्त उपायों में भारतीय कर कानूनों में विष्य में लागू किया जा सकता हो वश्यें उस उपायों के अध्याधीन करदाता को दिए गए लाभों के वार्त्यकेत्र के संबंध में दोनों सरकारों के बीच कोई करार मन्त्रव्याप्त किया जाए गया हो।

अनुच्छेद 24

1. एक संविदाकारी राज्य के शैटिटों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे काराधान अथवा न्यत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उस संविधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा भारपूर्ण हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के शैटिटों पर समान परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक गंविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थान पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में समान कार्य कलापों में लगे हुए उच्चमो पर लगया जाता है।

इस उपबंध में निहित किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी हैं, नागरिक हैंस्थित अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण वाराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छठ्टे, राहतें और घटीतियों प्रदान करने की वाद्य होंगा, जो वह अपने स्वंदेश के निवासियों को प्रदान करता है।

3. अनुच्छेद 9 के उपबंध, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 8 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 के उपबंध जहाँ लागू होते हैं उनको छोड़कर एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ऐसे उद्यम के करावेय लाभों का निवारण करने के प्रयोजनार्थ अदा किए गए व्याज, रायलिटियों तथा अन्य भूगतानों को उन समान परिस्थितियों के तहत काटौती योग्य माना जाएगा, यदि उनकी अदायगी प्रथमोलिंगित संविदाकार राज्य के किसी निवासी को गई हो।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से ग्राहिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अत्प्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोलिंगित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा न्यत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और न्यत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोलिंगित राज्य के अन्य इसी तरह के उद्यमों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में “कराधान” शब्द से तात्पर्य उन करों से है जो इस अनिमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 25

1. जहाँ कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है अथवा लगाया जाएगा, जो इस अनिमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन संविदाकारी राज्यों के घरेलू नियमों द्वारा उपविधित उपचारी उपायों के होने हए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरूप नहीं है, तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह रास्तिक है। यह मामला उस कार्य की प्रथम अधिगृहीत के तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण इस अनिमय के उपबंधों के अनुलेप कर भी होता है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी का अपहित उचित न हो और यदि वह स्वयं विसों संतोषजनन हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराठान के निवारण की दृष्टि से, जो इस अनिमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर महसूत द्वारा उस मामले की हल करने का प्रयास करेगा। प्राप्त हुए किसी भी समझौते की वर्गीकृति का हल करने का समय सीमा पर ध्यान न देने हुए संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के तहत, कार्यान्वयित किया जाएगा।

3. इस अनिमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई वर्तानाइयां अथवा अंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकारण के लिए परस्पर विचार-विमेश कर सकते हैं, जिनकी व्यवस्था इस अनिमय में नहीं की गई है।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में व्यक्ति अभियाप्त को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ एक दूसरे के साथ प्रत्यक्षतः पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

अनुच्छेद 26

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारों ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अनिमय के उपबंधों के अंतर्गत अनेक लाभों से संबंधित, जहाँ तक उनके अंतर्गत कराधान इस अनिमय के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, इस अनिमय के अथवा संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वयित करने अथवा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए अथवा ऐसे करों की जालजाजी को रोकने के लिए आवश्यक है। इस तरह से आदान-प्रदान की गई किसी भी सूचना को गोपनीय समझा जाएगा और इसे इस अनिमय में समाविष्य करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली अथवा उनको लागू करने अथवा उनके बारे में अभियोजन मंड़ी कार्यवाही करने में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्वाचन करने में लगे हुए व्यक्तियों अथवा प्राधिकरणों जिनमें व्यायालय भी शामिल हैं, को ही प्रकट किया जाएगा।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जिसमें कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डाला जाए :

- एक अथवा द्वारे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- ऐसी सूचना देना जो एक अथवा द्वारे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्तव्य नहीं है, अथवा
- ऐसी सूचना देना जिससे कोई व्यापारिक, व्याकुलायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यवसाय संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती है, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 27

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामन्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के प्रावृद्धानों के अन्तर्गत इस अभिसमय के कारण राजनियक अभिकर्ताओं अथवा कोई अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुच्छेद 28

1. इस अभिसमय को यथार्थ श्रीत्र टोकियो में अनुमर्यादित किया जाएगा और अनुमर्यादित के दशवें दिन का आदान-प्रदान किया जाएगा।

2. यह अभिसमय अनुपर्यन्त के दशवें दिन के आदान-प्रदान की तारीख के पश्चात् 30वें दिन को लागू होगा और इसका निपातनार प्रभाव होगा :

(क) जापान में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रवर्तित होता है उसके पश्चात्तीर्तीर्थ के जननी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् होने वाले किसी भी कारबोय वर्ष के लिए प्राप्त आय के संबंध में ; और

(ख) भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रवर्तित होता है उसके पश्चात्तीर्तीर्थ के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी भी “पूर्तवर्ती वर्ष” के लिए प्राप्त आय के संबंध में ।

3. आय पर करों के संबंध में दोहरे कारबोय के निवारण के लिए दिनांक 5 जनवरी, 1960 को नई दिल्ली में जापान और भारत के बीच हस्ताक्षर हुए करार उम आय के संबंध में समाप्त होने के साथ-साथ निप्रभावी भी हो जाएगा, जिसके बारे में यह अभिसमय पैराग्राफ 2 के उपर्योग अधिकारी लागू होता है।

अनुच्छेद 29

यह अभिसमय अनिवार्य कानून तक लागू रहेगा लेकिन दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष के जून मास के 30वें दिन को अथवा उससे पहले राजनियक साध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति का लिखित रूप में नोटिस दे सकता और ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निप्रभावी हो जाएगा :

(क) जापान में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके पश्चात्तीर्तीर्थ के जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी कारबोय वर्ष के लिए प्राप्त आय के संबंध में ; और

(ख) भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके पश्चात्तीर्तीर्थ के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी “पूर्तवर्ती वर्ष” के लिए प्राप्त आय के संबंध में ।

जिसके साथ में इसके लिए अरनी-प्रानी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

गत एक हजार नौ सौ नवामी के मार्च माह के मात्रवें दिन को नई दिल्ली में दिल्ली, जापानी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतिग्रन्थ में लिख दिया गया, जिसके नीनों पाठ समाप्त प्रामाणिक हैं। अर्थनिष्पत्ति में किसी प्रत्यार की मिलना 2 के लिए में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होता ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

जापान की सरकार
की ओर से

(इंशिटो नोट)

नं ६ दिसंबर, ७ मार्च, १९८९

मान्यवर,

भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कारबोय के परिधार और राजस्व भरवंचत को रोकने के लिए हुए उस अभिसमय, जिस पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं के अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 3 के उत्तराधिकार (ग) का हावाला देने और भारत गणराज्य की सरकार की ओर से भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच हुए निम्नलिखित समझौते की पुष्टि करने का मुख्य गौरव प्राप्त हुआ है :—

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की निम्नलिखित घाराओं में विनिर्दिष्ट उपाय, जिनका उल्लेख उक्त पैराग्राफ में किया गया है, ये हैं : “भारत में आर्थिक विकास की उन्नति के लिए अभियानित विशेष प्रोत्साहनकारी उपाय जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।”

(i) धारा 10 (15)(IV)

—जो कतिपय व्याज पर से छठ से संबंधित है

(ii) धारा 10क

--जो मूर्ति व्यापार क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपकरणों की वावन विशेष उपचंग से संबंधित है;

(iii) धारा 32क्ष

--जो मंत्रवं तथा मणीनगी आदि में निवेश के मंत्रवं में विविध व्यापार निवेश खाते से संबंधित है.

(iv) धारा 80जज

--जो पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपकरणों या होटल कारोबार से प्राप्त लाभों और अभिनाभियों की वावन कटौती से संबंधित है.

(v) धारा 80झ

--जो किसी निश्चित तारीख के पश्चात औद्योगिक उपकरणों में लाभों और अभिनाभियों को वावन कटौती आदि से संबंधित है

मुझे जापान की सरकार की ओर से पूर्वोत्तराता ही पहुंच पुष्ट करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है

मैं आपके महामहिम को ग्राही उच्चात्म दृष्टिकोण का प्राप्तवासन देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना हूँ।

(ह०/-)

जो. एन. ज़. गा.

अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वित्त मंत्रालय

महामहिम श्री एड जीरो नोडा

भारत में जापान के असाधारण
एवं पूर्णाधिकारी राजदूत

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1989

(ह०/-)

एड जीरो नोडा

भारत में जापान के असाधारण एवं
पूर्णाधिकारी राजदूत

मूझे आज की तारीख के आपके महामहिम की टिप्पणी को पावती देने का गौरव प्राप्त हुआ है जो निम्न प्रकार से एठनीय है:-

"भारत गणराज्य को सरकार और जापान सरकार के बोच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधार के परिहार और गजस्व अपवंचन को शेकरे के लिए हुए उस अभिसमय, जिस पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं, के

अनुच्छेद 23 के पेरायाक 3 के उत्तरपैरायाक (ग) का हवाला देने और भारत गणराज्य की सरकार को और से भारत गणराज्य को सरकार और जापान की सरकार के बोच हुए निम्नलिखित समझौते को पुष्ट करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है:-

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का निम्नलिखित धारा और में निर्मित उपाय, जिनमा उल्लेख उक्त पैरायाक में किया गया है, ये हैं: "भारत में आर्थिक विरोप को उत्तरि के लिए अधिकलिप्त विशेष प्रोत्साहनकारी उपाय जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने को न रख से प्रभावी होगे।"

(i) धारा 10(15)(iv)

--जो कांपिय व्याज पर कर में छूट ने मंत्रवं है;

(ii) धारा 10क

--जो मूर्ति व्यापार-क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपकरणों का वावन विशेष उपचंग से संबंधित है;

(iii) धारा 32क्ष

--जो मंत्रवं तथा मणीनगी प्रादि में निवेश के पश्च पर में विनियान निवेश खाते आदि से संबंधित है;

(iv) धारा 80जज

--जो पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपकरणों या होटल कारोबार से प्राप्त लाभों को वावन कटौती से संबंधित है;

(v) 80झ

--जो किसी निश्चित तारीख के पश्चात् औद्योगिक उपकरणों से लाभों और अभिनाभियों की वावन कटौती आदि से संबंधित है;

मुझे जापान की सरकार की ओर से पूर्वोत्तराता ही पहुंच पुष्ट करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है।"

इसके अधिकतम, जापान सरकार को भी आपके महामहिम की टिप्पणी में अन्तर्विष्ट समझौते का पुष्ट करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है।

मैं आपके महामहिम को ग्राही उच्चात्म दृष्टिकोण का प्राप्तवासन देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाता हूँ।

महामहिम श्री जो. एन. गृहा
अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1989

मान्यवर,

मुझे जापान सरकार और भारत गणराज्य को भरपार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे करधान के परिवार और राजस्व अपवंशन को रोकने के लिए समझौता हुए। उम्मीदवारों को इस अभिसमय का हवाला देने, जिस पर आज हस्ताक्षर हुए हैं और जापान सरकार को ओर से दोनों सरकारों के बीच हुए निम्नलिखित समझौते की पुष्टि करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

1. इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) के संदर्भ में किन्हीं भी करों को, जो कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत लगाए गए अतिकरों के समान हैं अथवा सारतः उसी प्रकार के हैं लेकिन वाद में जिन्हें सम्प्रत कर दिया गया और जिन्हें इस अभिसमय के हस्ताक्षर होने को तारीख के पश्चात् भारत में लागू किया गया है, इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित परों के समान अथवा सारतः उसी प्रकार के कर समझा जाएगा।

2. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) के संदर्भ में “कर” शब्द में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संबंध में देय है जिसके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो इन करों के संबंध में लगाये गये किसी दंड को दर्शाता है।

3. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 से पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (झ) के संदर्भ में भारत के मामले में “अधिक” पद में कोई भागीदारिता और कोई हिन्दू अविभाजित परिवार भी शामिल होगा।

4. इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में उसमें उल्लिखित “सेवाएँ अथवा सुविधाएँ” शब्दों में विनिज तेलों को खोज करने, समुपयोजन करने अथवा उनमें निष्कर्षण में प्रयुक्त किए गए अथवा प्रयुक्त किए जाने के लिए किराए पर लिए जाने वाले संप्रत्र तथा मणितरों को आपूर्ति भी शामिल होगी।

5. ऐसा समझा जाता है कि इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 6 के उपबंध, किसी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं की डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए सुविधाओं के उपयोग के लिए अथवा डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के उस स्टॉक के रख-रखाव हेतु लागू होंगे जब तक कि ऐसे माल अथवा पण्य वस्तुओं को बिक्री उम्मीदवारों द्वारा माल के लेन-देन के सौदों से उद्भूत उन अभिलाभों को

जिनमें स्थायी मस्थापन अन्तर्गत है, स्थायी मस्थापन के कारण उम्मीदवारों सीमा तक उद्भूत हुआ समझा जाएगा जो लेन-देन के उन सौदों में स्थाई मस्थापन होता है। यह भी समझा जाता है कि अभिलाभों को उत्तर उल्लिखित यथा तक स्थायी मस्थापन के कारण उत्पन्न हुआ समझा जाएगा, भले ही प्रज्ञनमत माल को बिक्री अथवा सेवाओं की व्यवस्था में संविधित परिवार अथवा आईंग रथायी सस्थापन की बजाए उम्मीदवार के सम्बूधार प्रतिपादन कार्यालय के सामने किया जाता है अथवा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

7. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि भारत में उक्त पैराग्राफ में वयाउलिखित कार्यकारी और मामान्य प्रणालीनिक खर्चों के संबंध में कटौतियां भारत के आन्तरिक कानूनों के अनुमार, अनुमत्य होंगी लेकिन गेसों कटौतियों का मात्रा किसी भी दण में इस अभिसमय के हस्ताक्षर को तारीख से लागू भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य रकम से कम नहीं होगी।

8. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में किसी उद्यम के किसी स्थायी संस्थापन होता है उस उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त राशियों अथवा प्रामाणित राशियों (वारस्तिक खर्चों को प्रतिपूति से भिन्न) के संबंध में काई कटौतों नहीं दो जाएंगी :

(क) पेटेट अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के लिए अथवा जानागारी के इस्तेमाल के लिए आय विवरणों में रखलियों, फोसों अथवा इसी प्रकार के अन्य भुगतान,

(ख) निष्पादित विनियोग सेवाओं अथवा प्रवध-व्यवस्था के लिए कमीजन अथवा अन्य प्रमार, और

(ग) स्थायी मस्थापन को उधार दी गई रकमों पर ब्याज, सिवाय उस मामले में जहां वह उद्यम, कोई बैंकिंग संस्था है।

9. इस अभिसमय के अनुच्छेद 8 के संदर्भ में,

(i) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा बायुयानों के संचालन के संबंध में अस्थायी रूप से निशेषित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा बायुयानों के संचालन से प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध में अनुच्छेद 11 के उपबंध लागू नहीं होंगे, और

(ii) जलयानों अथवा बायुयानों के संचालन से प्राप्त हुई आय में, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य वस्तुओं के परिवहन के संबंध में कंटेनरों (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रैलर्स तथा उनसे संबंधित उपकरण भी शामिल हैं) के इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किराए से प्राप्त आय भी शामिल हैं।

6. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि उम्मीदवारों के लिए “स्थायी मस्थापन के कारण प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः” पद का प्रयोग करते हुए माल के लेन-देन के सौदों से उद्भूत उन अभिलाभों को

10. इस अभिसमय के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, यदि भारत को कोई स्वार्थी प्राप्तिकरण, इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तार्ख के बाद जापान में उद्यम करके पर्याप्त रूप से समान-स्तरहृषि के कोई कार लगाता है तो दोनों गवर्नर एवं नारसाचिक आधार पर ऐसी रौप्ति से, जैना कि वे उचित समझी हैं, अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 5 का संशोधन करने के लिए परामर्श करेंगी।

मुझे आपके महामहिम को सरकार की ओर से पूर्वोक्त समझोते की सहर्ष पुष्टि करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है।

मैं आपके महामहिम को अपने उच्चतम दृष्टिकोण के ग्राइडमन का पुनः स्मरण करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाता है।

ह-

एइजोठो नोडा,

भारत में जापान के अमाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत

महामहिम श्री जी.एन. गुप्ता,

अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1989

मान्यवर,

मुझे आज को तार्ख के आपके महामहिम को टिप्पणी की पावती स्वीकारने वा गौरव प्राप्त हुआ है जो निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगी :

“मुझे जापान सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आय पर वरों के संबंध में दोहरे काराधान के परिहार और राजस्व अपव्यन को रोकने के लिए समझ हुए उस अभिसमय का हवाला देने, जिस पर आज हस्ताक्षर हुए हैं और जापान सुरकार की ओर से दोनों सरकारों के बीच हुए निम्नलिखित समझोते की पुष्टि करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

1. इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) के संदर्भ में किसी भी वरोंको, जो कपर्न (लाभ) अतिकार इंटिनियम 1964 के अन्तर्गत लगाए गए अतिकरों के समान हैं अथवा सारल: रसी प्रकार के हैं लेकिन बाद में जिन्हें समाप्त कर दिया गया और जिन्हें इस अभिसमय के हस्ताक्षर होने की तार्ख के पश्चात सारल में लाग दिया गया है, इस अधिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित करों के समान प्रवता सारल : उस प्रकार के कर समझा जाएगा ।

2. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (घ) के संदर्भ में ‘कर’ शब्द में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन वरों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संबंध में देव है। जिसके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो इन वरों के संबंध में लगाये गये किसी दंड का दर्शना है।

3. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ङ) के संदर्भ में, भारत के मामले में “व्यवित” पद में कोई भागीर दारिता और कोई हिन्दू अदिवासित परिवार भी शामिल होगा।

4. इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में उसमें उल्लिखित “संवार्द्ध अथवा सुविधार्द्ध” सर्दों में खनिज तेलों का खोज करने, समुपयोजन करने अथवा उनके निष्कर्षण में प्रयुक्त किए गए अथवा प्रयुक्त किए जाने के लिए किराए पर लिए जाने वाले संयंव तथा मशीनरी को आपूर्त भी शामिल होगी।

5. ऐसा समझा जाता है कि इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 6 के उपसंबंध किसी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं की डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए सुविधाओं के उपयोग अ लिए अथवा डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के उस स्टाक के रख-रखाव हेतु लागू होंगे जब तक कि ऐसे माल अथवा पण्य वस्तुओं की विक्री उस दूसरे संविदाकारी राज्य में होती है।

6. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि उस “स्थायी संस्थापन के कारण प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः” पद का प्रयोग करते हुए माल के लेन-देन के सर्दों से उद्भूत रूप अफिलाभों को जिसमें स्थायी संस्थापन अन्तर्गत है, स्थायी संस्थापन के कारण उस सीमा तक उद्भूत हुआ समझा जाएगा जो लेन-देन के उन सर्दों में स्थायी संस्थापन द्वारा किए गए कार्यों के लिए समुचित होगा यह भी समझा जाता है कि अफिलाभों को ऊपर उल्लिखित सीमा तक स्थायी संस्थापन के कारण उद्भूत हुआ समझा जाएगा, भले ही प्रश्नगत माल की विक्री अथवा रोवाओं की व्यक्त्य से संबंधित संविदा अथवा आर्डर स्थायी संस्थापन की वजाए उस उद्यम के समृद्धपार स्थित प्रथान कार्यलय के सामने किया जाता है अथवा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

7. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि भारत में उक्त पैराग्राफ में यथा-उल्लिखित वार्यवारी और सामान्य प्रशासनिक खर्चों के संबंध में कर्टानियों भारत के आन्तरिक वानों के अनुसार, अन्तर्मत्य होनी लेकिन ऐसी कर्टानियों की मात्रा किसी भी दशा में इस अभिसमय के हस्ताक्षर की तार्ख से लागू भागीर्त्य आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुभव्य रकम से कम नहीं होगी।

8. इस अधिसमय के अनुच्छेद 7 के पंराग्राफ 3 के संदर्भ में किसी उद्यम के किसी स्थायी गंस्थापन द्वारा उस उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके किसी अन्य वार्षिकीयों को निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त राशियों अथवा प्रभारित राशियों (वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति से मिल) के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी :

(क) पेटेट अथवा अन्य अधिकारी के इस्तेमाल के लिए अथवा जानकारी के इस्तेमाल के लिए आय दिवारणी में राष्ट्रियों, फ़ीसों अथवा इसी प्रकार के अन्य भुगतान,

(ख) निष्पादित दिग्गिट सेवाओं अथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभार, और

(ग) स्थार्यी संस्थापन को उद्धार द्वारा द्वारा रकमों पर ब्याज, गिवाय उस मामले में जहां वह उद्यम कोई वैकिण संस्था है।

9. इस अधिसमय के अनुच्छेद 8 के सदम में,

(i) अन्तरराष्ट्रीय याताथात में जलधारों अथवा वायुयानों के संचालन के संबंध में अस्थायी रूप से निष्पेक्ष निषियों पर ल्याज को ऐसे जलधारों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा और ऐसे ल्याज के संबंध में अनुच्छेद 11 के उपर्युक्त लागू नहीं होंगे, और

(ii) जलधारों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त हुई आय में, अन्तरराष्ट्रीय याताथात में नोल अथवा पृथ्य वस्तुओं के परिवहन के संबंध में कन्टेनरों (जिसमें कन्टेनरों के परिवहन के लिए ट्रैलर्स तथा उनसे संबंधित उपकरण भी शामिल हैं) के इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किरणे से प्राप्त आय भी शामिल है।

10. इस अधिसमय के अनुच्छेद 8 के पंराग्राफ 5 के सदम में, यदि भारत कोई स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद जापान में उद्यम-कर के पर्याप्त रूप से समान स्वरूप के कोई कर लगाता है तो दोनों सरकारें एक-पारस्परिक आधार पर ऐसी रूपति से, जैवाकि वे उचित समझती हैं, अनुच्छेद 8 के पंराग्राफ 5 का संशोधन करने के लिए परामर्श करेंगी।

मुझे आपके महामहिम की सरकार की ओर से पूर्वोक्त समझते की महर्व पुष्ट करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी गोरव प्राप्त हुआ है।'

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की सरकार की ओर से आपके महामहिम की ठिक्की में अन्तर्विट समझते की पुष्ट करने का भी मुझे गोरव प्राप्त हुआ है।

मैं आपके महामहिम को अपने उच्चाम दृष्टिकोण के आवधासन का पुनः स्मरण करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना हूँ।

ह.

जी. एन. गुप्ता

अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रबन्ध कर बोर्ड
वित्त मंत्रालय

महामहिम श्री एइजीरो नोडा, भारत में जापान के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत

[अधिसूचना न. 8587/फा. ग.-506/69/81-एफ टी. डी.]

पा. के. अप्पाचु, मंत्रिमंडल सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1990

INCOME-TAX

G.S.R. 101(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 29th December, 1989 after the exchange of Instruments of Ratification as required by paragraph 1 of Article 28 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of Japan,

Desiring to conclude a new Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Have agreed as follows :

Article 1

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

1. The taxes which are the subject of this Convention are :

(a) In Japan :

- (i) the income tax; and
- (ii) the corporation tax (hereinafter referred to as "Japanese tax");

(b) In India:

the income-tax including any surcharge thereon (hereinafter referred to as "Indian tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, those referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such change.

Article 3

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "Japan", when used in a geographical sense, means all the territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which Japan has jurisdiction in accordance with international law and in which the laws relating to Japanese tax are in force;
- (b) the term "India" means the territory of India including the territorial sea and any other maritime zone in which India has sovereign rights according to the Indian law and in accordance with international law;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Japan or India, as the context requires;
- (d) the term "tax" means Japanese tax or Indian tax, as the context requires;
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean

respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means :

(i) in respect of Japan :

all individuals possessing the nationality of Japan and all juridical persons created or organized under the laws of Japan and all organizations without juridical personality treated for the purposes of Japanese tax as juridical persons created or organized under the laws of Japan ;

(ii) in respect of India :

(aa) all individuals possessing the nationality of India;

(bb) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in India;

(i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; and

(j) the term "competent authority" means :

(i) in Japan, the Minister of Finance or his authorized representative;

(ii) in India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or their authorized representative.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which this Convention applies.

Article 4

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention.

Article 5

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- a place of management;
- a branch;
- an office;
- a factory;
- a workshop;
- a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
- a store or other sales outlet; and
- an installation or structure used for the exploration of natural resources, but only if so used for a period of more than six months.

3. A building site or construction, installation or assembly project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it carries on supervisory activities in that Contracting State for more than six months in connection with a building site or construction, installation or assembly project which is being undertaken in that Contracting State.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4 an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in that Contracting State for more than six months in connection with the exploration, exploitation or extraction of mineral oils in that Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;
- the maintenance for a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

7. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if

- he has and habitually exercises in that Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 6 which, if exercised through a fixed place of business, would

not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph;

- he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- he habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprise controlling, controlled by, or subject to the same common control as that enterprise.

8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immovable property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources, ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are

incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

1. Profits from the operation of aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. Profits from the operation of ships in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, such profits may be taxed in the other Contracting State from which they are derived during a period of first ten taxable years or "previous years", as the case may be, for which this Convention shall have effect provided that the tax so charged shall not exceed :—

(a) during the first five years, 50 per cent,

(b) during the remaining five years, 25 per cent, of the tax otherwise imposed by the taxation law of that other Contracting State.

4. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, also apply to the enterprise tax in Japan and to any tax similar to the said enterprise tax if and when such a tax is imposed in India.

Article 9

1. Where :

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but

for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and where the competent authorities of the Contracting States agree upon consultation, that all or part of the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. In determining such a justement, due regard shall be had to the other provisions of this Convention.

Article 10

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed bases situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other Contracting State.

Article 11

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws

of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a bank; and
- (b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government, or by any resident of the other Contracting State with respect to debt-claims guaranteed or indirectly financed by the Government of that other Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

4. For the purposes of paragraph 3, the terms "the Central Bank" and "financial institution wholly owned by the Government" mean :

- (a) the case of Japan :
 - (i) the Bank of Japan;
 - (ii) the Export-Import Bank of Japan;
 - (iii) the Overseas Economic Cooperation Fund;
 - (iv) the Japan International Cooperation Agency; and
 - (v) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of Japan as may be agreed upon from time to time between the Government of the two Contracting States;
- (b) in the case of India :
 - (i) Reserve Bank of India;
 - (ii) Export-Import Bank of India;
 - (iii) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of India as may be agreed upon from time to time between the Government of the two Contracting States.

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prize attacking to such securities, bonds or debentures.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division or a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with

which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only or to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments and to any individual for independent personal services referred to in Article 14, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provisions of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees

for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of any property, other than immovable property, forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of any property, other than immovable property, pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

3. Unless the provisions of paragraph 2 are applicable gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and any property, other than immovable property, pertaining to such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 4, shall be taxable only in that Contracting State.

Article 14

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities or he is present in that other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days during any taxable year or "previous year", as the case may be. If he has such a fixed base or remains in that other Contracting State for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other Contracting State during the aforesaid period or periods.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if :

- (a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during any taxable year or "previous year", as the case may be ; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State ; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

Article 16

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by an individual who is a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, and a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

Such income shall, however, be exempt from tax in that other Contracting State if such activities are exercised by an individual who is a resident of the first-mentioned Contracting State pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.

2. Where income in respect of personal activities exercised in a Contracting State by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person who is a resident of the other Contracting State, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the first-mentioned Contracting State.

Such income shall, however, be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State if such activities are exercised pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.

Article 18

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that Contracting State.

Article 19

- 1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, to an individual in respect of services rendered to that Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that other Contracting State ; who :
 - (i) is a national of that other Contracting State ; or
 - (ii) did not become a resident of that other Contracting State solely for the purpose of performing the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds to which contributions are made by, a Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, to an individual in respect of services rendered to that Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

Article 20

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that first-mentioned Contracting State.

Article 21

1. A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other accredited educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated thereon, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 23

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting State except where express provisions to the contrary are made in this Convention.

2. Double taxation shall be avoided in the case of India as follows :

(a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Japan, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the Japanese tax paid in Japan,

whether directly or by deduction. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income-tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Japan. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income-tax paid in Japan shall be allowed in the first instance from income-tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.

(b) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Japan, India may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income-tax that part of the income-tax which is attributable, as the case may be, to the income derived from Japan.

3. Subject to the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese tax or tax payable in any country other than Japan :

(a) Where a resident of Japan derives income from India which may be taxed in India in accordance with the provisions of this Convention, the amount of Indian tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Japanese tax which is appropriate to that income.

(b) Where the income derived from India is a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Japan and which owns not less than 25 per cent either of the voting shares of the company paying the dividend, or of the total shares issued by that company, the credit shall take into account the Indian tax payable by the company payable the dividend in respect of its income.

(c) For the purposes of the credit referred to in subparagraphs (a) and (b) above, there shall be deemed to have been paid by the tax payer the amount which would have been paid as Indian tax under the laws of India and in accordance with this Convention if the Indian tax had not been reduced or relieved in accordance with the special incentive measures designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Convention or which may be introduced in future in the Indian tax laws in modification of or in addition to the existing measures, provided that an agreement is made between the two Governments in respect of the scope of the benefit accorded to the tax payer by the said measures.

Article 24

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 8 or Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 25

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the provisions of this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs of this Article.

Article 26

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the provisions of this Convention, or for the prevention of fiscal evasion or fraud with respect to such taxes. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall be disclosed only to persons or authorities including courts, involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the taxes covered by the Convention or the determination of appeals in relation thereto.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; or

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Tokyo as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of instruments of ratification and shall have effect:

- (a) in Japan : as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and
- (b) in India : as regards income for any "previous year" beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

3. The Agreement between Japan and India for the Avoidance of Double Taxation in respect of Taxes on Income signed at New Delhi on January 5, 1960 shall terminate and cease to have effect in respect of income to which this Convention applies under the provisions of paragraph 2.

Article 29

This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before the thirtieth day of June of any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

- (a) in Japan : as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given; and
- (b) in India : as regards income for any "previous year" beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done at New Delhi in duplicate on this Seventh day of March, 1989 in the Hindi, Japanese and English languages, all the three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

For the Government

of the Republic of India.

Sd/-

(G. N. Gupta)

For the Government
of Japan

Sd/-

(Eijiro Nojiri)

New Delhi, March 7, 1989

Excellency,

I have the honour to refer to sub-paragraph (c) of paragraph 3 of Article 23 of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm on behalf of the Government of the Republic of India, the following understanding reached between the Government of the Republic of India and the Government of Japan:

The measures set forth in the following sections of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) of India, are "the special incentive measures designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Convention" referred to in the said sub-paragraph;

- (i) Section 10(15) (iv).—relating to exemption from tax on certain interest;
- (ii) Section 10A.—relating to special provision in respect of newly established industrial undertakings in free trade zones;
- (iii) Section 32AB.—relating to investment deposit account, etc. with respect to investment in plant and machinery etc.;
- (iv) Section 80HH.—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in backward areas;
- (v) Section 80I.—relating to deduction in respect of profits and gains from industrial undertakings after a certain date, etc.;

I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm the foregoing understandings on behalf of the Government of Japan.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

G. N. Gupta,
Chairman.

Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance.

His Excellency Mr. Eijiro Noda.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Japan to India.

New Delhi, March 7, 1989

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date which reads as follows:

"I have the honour to refer to sub-paragraph (c) of paragraph 3 of Article 23 of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm, on behalf of the Government of the Republic of India, the following understanding reached between the Government of the Republic of India and the Government of Japan:

The measures set forth in the following sections of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) of India, are "the special incentive measures designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Convention" referred to in the said sub-paragraph;

- (i) Section 10(15) (iv) relating to exemption from tax on certain interest;
- (ii) Section 10A.—relating to special provision in respect of newly established industrial undertakings in free trade zones;

- (iii) Section 32AB.—relating to investment deposit account, etc. with respect to investment in plant and machinery etc.;
- (iv) Section 80HH.—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in backward areas;
- (v) Section 80I.—relating to deduction in respect of profits and gains from industrial undertakings after a certain date, etc.;

I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm the foregoing understanding on behalf of the Government of Japan."

I have further the honour to confirm the understanding contained in Your Excellency's Note, on behalf of the Government of Japan.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Eijiro Noda,
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan
to India.

His Excellency Mr. G. N. Gupta,
Chairman,
Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance.

New Delhi, March 7, 1989

Excellency,

I have the honour to refer to the Convention between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm, on behalf of the Government of Japan, the following understanding reached between the two Governments :

1. With reference to sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 2 of the Convention, any taxes which are identical or substantially similar to the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 but abolished subsequently, and which are imposed in India after the date of signature of the Convention shall be regarded as the identical or substantially similar taxes referred to in paragraph 2 of Article 2 of the Convention.

2. With reference to sub-paragraph (d) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, the term "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which the Convention applies or which represents a penalty imposed relating to these taxes.

3. With reference to sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, in the case of India, the term "person" shall include a partnership and a Hindu Undivided Family.

4. With reference to paragraph 5 of Article 5 of the Convention, the term "services or facilities" referred to therein shall include the supply of plant and machinery on hire used or to be used in the exploration, exploitation or extraction of mineral oils.

5. It is understood that the provisions of paragraph 6 of Article 5 of the Convention shall apply to the use of facilities solely for the purpose of delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise or to the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of delivery unless sales of such goods or merchandise are effected in that other Contracting State.

6. With reference to paragraph 1 of Article 7 of the Convention, it is understood that by using the term "directly or indirectly attributable to that permanent establishment", profits arising from transactions in which the permanent establishment has been involved shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the extent appropriate to the part played by the permanent establishment in those transactions. It is also understood that profits shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the above-mentioned extent, even when the contract or order relating to the sale or provision of goods or services in question is made or placed directly with the overseas head office of the enterprise rather than with the permanent establishment.

7. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, it is understood that in India the deductions in respect of the executive and general administrative expenses as referred to in the said paragraph shall be allowed in accordance with the domestic law of India, but such deductions shall in no case be less than what are allowable under the Indian Income-tax Act as effective on the date of signature of the Convention.

8. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, no deduction shall be allowed in respect of amounts paid or charged (other than reimbursement of actual expenses) by a permanent establishment of an enterprise to the head office of the enterprise or any other offices thereof, by way of :

- (a) royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or for the use of know-how;
- (b) commission or other charges, for specific services performed or for management; and
- (c) interest on moneys lent to the permanent establishment; except where the enterprise is a banking institution.

9. With reference to Article 8 of the Convention,

- (i) interest on funds temporarily deposited in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest: and
- (ii) income from the operation of ships or aircraft includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

10. With reference to paragraph 5 of Article 8 of the Convention, if a local authority of India introduces any taxes of a character substantially similar to the enterprise tax in Japan after the date of signature of the Convention, the two Governments shall consult with a view to amending paragraph 5 of Article 8 on a reciprocal basis in such manner as may be considered appropriate.

I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm the foregoing understanding on behalf of Your Excellency's Government.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Sd/-

Fujiro Noda

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan to
India

His Excellency Mr. G. N. Gupta
Chairman,
Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance.

New Delhi, March 7, 1989

Excellency.

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Convention between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm, on behalf of the Government of Japan, the following understanding reached between the two Governments:

1. With reference to sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 2 of the Convention, any taxes which are identical or substantially similar to the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 but abolished subsequently, and which are imposed in India after the date of signature of the Convention shall be regarded as the identical or substantially similar taxes referred to in paragraph 2 of Article 2 of the Convention.

2. With reference to sub-paragraph (d) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, the term "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which the Convention applies or which represents a penalty imposed relating to these taxes.

3. With reference to sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, in the case of India, the term "person" shall include a partnership and a Hindu Undivided Family.

4. With reference to paragraph 5 of Article 5 of the Convention, the term "services or facilities" referred to therein shall include the supply of plant and machinery on hire used or to be used in the exploration, exploitation or extraction of mineral oils.

5. It is understood that the provisions of paragraph 6 of Article 5 of the Convention shall apply to the use of facilities solely for the purpose of delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise or to the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of delivery unless sales of such goods or merchandise are effected in that other Contracting State.

6. With reference to paragraph 1 of Article 7 of the Convention, it is understood that by using the term "directly or indirectly attributable to that permanent establishment", profits arising from transactions in which the permanent establishment has been involved shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the extent appropriate to the part played by the permanent establishment in those transactions. It is also understood that profits shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the above-mentioned extent, even when the contract or order relating to the sale or provision of goods or services in question is made or placed directly with the overseas head office of the enterprise rather than with the permanent establishment.

7. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, it is understood that in India the deductions in respect of the executive and general administrative expenses as referred to in the said paragraph shall be allowed in accordance with the domestic law of India, but such deductions shall in no case be less than what are allowable under the Indian Income-Tax Act as effective on the date of signature of the Convention.

8. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, no deduction shall be allowed in respect of amounts paid or charged (other than reimbursement of actual expenses) by a permanent establishment of an enterprise to the head office of the enterprise or any other offices thereof, by way of :

- (a) royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or for the use of know-how;

- (b) commission or other charges, for specific services performed or for management; and
- (c) interest on moneys lent to the permanent establishment; except where the enterprise is a banking institution.

9. With reference to Article 8 of the Convention,

- (i) interest on funds temporarily deposited in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest; and
- (ii) income from the operation of ships or aircraft includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

10. With reference to paragraph 5 of Article 8 of the Convention, if a local authority of India introduces any taxes of a character substantially similar to the enterprise tax in Japan after the date of signature of the Convention, the two Governments shall consult with a view to amending para-

graph 5 of Article 8 on a reciprocal basis in such manner as may be considered appropriate.

I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm the foregoing understanding on behalf of Your Excellency's Government."

I have further the honour to confirm the understanding contained in Your Excellency's Note, in behalf of the Government of the Republic of India.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Sd/-

G. N. Gupta,
Chairman,
Central Board of Direct Taxes.
Ministry of Finance.

His Excellency Mr. Eijiro Noda,
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan to
India.

[No. 8587/F. No. 506/69/81-FTD]

P. K. APPACHOO, Lt. Secy.